न्यूज डायरी

सू की की पार्टी के 2 बड़े नेताओं को 90 और 75 साल कैद की सजा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) बैंकॉक। म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की की राजनीतिक पार्टी के दो सदस्यों को करप्शन के मामले में दोषी ठहराने के बाद 90 और 75 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस साल एक फरवरी को सैन्य तख्तापलट में सू की की 'नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी' को सत्ता से बाहर करने के बाद पार्टी के किसी सदस्य को सुनाई गई यह सबसे बड़ी सजा है। वकील जॉ मिन हलिंग ने बताया कि कायिन राज्य के पूर्व योजना मंत्री थान नैंग को एक अदालत ने भ्रष्टाचार के 6 आरोपों में दोषी ठहराया और उन्हें 90 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, कायिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सू की की राजनीतिक पार्टी के शीर्ष सदस्य नैन खिन हत्वे म्यिंत को पांच आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया और प्रत्येक के लिए 15–15 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

आतंकियों को पाकिस्तान का ऑफर, कीजिए ये काम तो इमरान सरकार देगी सम्मान

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि सरकार हिंसा छोड़कर संविधान को अपनाने के इच्छुक आतंकियों को एक मौका देना चाहती है। चौधरी ने यहां एक कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से यह बात कही। बैठक में, देश में वर्तमान सुरक्षा हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से संबद्ध कुछ समूह हिंसा छोड़ना चाहते हैं और सरकार भी उन्हें सामान्य जीवन में लौटने का एक मौका देना चाहती है। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक दिन पहले सांसदों को राष्ट्रीय सुरक्षा हालात के बारे में जानकारी दी थी। चौधरी ने सोमवार को कहा था कि सरकार और प्रतिबंधित संगठन के बीच संघर्षविराम समझौता हुआ है। बता दें कि दो दिन पहले ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने पिछले 14 वर्षों में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर कई हमलों के जिम्मेदार एक प्रमुख आतंकवादी संगठन के साथ एक महीने के संघर्ष विराम की घोषणा की है।

जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच जल्द बैठक होने की उम्मीद

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी लीडर शी चिनफिंग के बीच एक वर्चुअल बैठक जल्द अगले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस मामले पर जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने रायटर को यह जानकारी दी। हालांकि, बैठक अगले हफ्ते होगी? इस बात से व्हाइट हाउस और वाशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ताओं ने पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। बाइडन प्रशासन के शुरुआती दौर में चीन के साथ संयुक्त अमेरिकी राजनयिक आदान–प्रदान ने सहयोगियों को अच्छे संकेत नहीं दिए और अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि शी के साथ सीधा जुड़ाव दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को संघर्ष की ओर बढ़ने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है।

अमेरिका में 18 या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज देने की तैयारी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वाशिंगटन। दुनियाभर में कोरोना महामारी का कहर अभी भी खत्म नहीं हो पाया है। अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के कई भागों में कोरोना वायरस के मामले लगातार आ रहे हैं अमेरिका में अब कोरोना के खिलाफ बूस्टर यानी वैक्सीन के तीसरे डोज को लगाने का अभियान चल रहा है। इसके तहत अमेरिका ने अब अपनी सभी वयस्क आबादी को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी फाइजर ने मंगलवार को अमेरिकी नियामकों से 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की अनुमति देने के लिए कहा। अमेरिका की ओर से ये कदम इस वजह से उठाया गया है क्योंकि वहां छुट्टियां और ट्रैवेल शुरू होने वाला है। ऐसे में लोगों की बढ़ती भीड़ के साथ कोरोना वायरस के फैलने का भी खतरा बढ़ सकता है। इसको देखते हुए अमेरिका ने ये फैसला लिया है।

पीएम इमरान खान पर बिफरे चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान

आर्मी स्कूल नरसंहार मामले में किया तलब

निंदा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले से ही विपक्ष के आरोपों और देश की माली हालत ने उनकी स्थिति नाजुक कर रखी है वहीं अब 2014 में हुए पेशावर स्कूल नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है। 16 दिसंबर 2014 को तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के छह आतंकियों ने पेशावर स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कर 147 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मरने में 132 बच्चे थे। इस हमले की पूरी दुनिया ने कड़े स्वर में निंदा की थी।

इस मामले में की सुनवाई चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान गुलजार अहमद के नेतृत्व वाली बैंच कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सीजेपी ने एटार्नी जनरल खालिद जावेद खान को निर्देश दिए थे कि इस हमले में मारे गए बच्चों के परिजनों की शिकायतों को दूर करने के लिए जो

कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। आज हुई सुनवाई में सीजेपी ने एटार्नी जनरल से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ने कोर्ट के आदेश को पढ़ा है। इस पर जावेद ने बताया कि कोर्ट का आदेश प्रधानमंत्री को नहीं भेजा गया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी दे दी गई थी।

जावेद के इस बयान पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान के रवैये की कड़ी निंदा की। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या यही गंभीरता का स्तर है। सीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन लगाया जाए हम खुद उनसे बात करेंगे। इस तरह का रवैया नहीं चल सकता है। इस पर जावेद ने गलती स्वीकारते हुए सरकार की तरफ से कोर्ट के समक्ष माफी भी मांगी।

पिछली सुनवाई के दौरान इस हमले में मारे गए बच्चों के परिजनों ने मांग की थी कि इस मामले में उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए जिन्होंने स्कूल की सुरक्षा में कोताही बरती। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख ऐसे समय में अपनाया है जब पाकिस्तान की सरकार आतंकी संगठनों से समझौते को लेकर बात कर रही है। इसमें टीटीपी भी शामिल है। टीटीपी समझौता वार्ता के मद्देनजर सीजफायर की घोषणा की है।

हालांकि विपक्ष ने इस पर पाकिस्तान सरकार को चौतरफा घेरा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान उस टीटीपी से समझौते की बात कर रहे हैं जिन्होंने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और बेगुनाह बच्चों का खून बहाया है। विपक्ष का एक सवाल ये भी है कि समझौते की सूरत में इस मामले का क्या होगा और जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनका क्या होगा। बता दें कि वर्ष 2007 से ही टीटीपी पाकिस्तान के कई इलाकों में एक्टिव है। टीटीपी ने पाकिस्तान में हुए कई बड़े धमाकों की भी जिम्मेदारी ली है।

परमाणु रिएक्टर शुरू करने जा रहा है फ्रांस

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) पेरिस। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए फ्रांस इसकी रोकथाम के लिए बड़ा प्रयास करने की तैयारी में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि 'ग्लोबल वार्मिंग' के लिए जिम्मेदार उत्सर्जन को कम करने के अपने वादों को पूरा करने के प्रयासों के तहत फ्रांस अपने नए परमाणु रिएक्टर का निर्माण शुरू करेगा।

ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी और रूस सहित वैश्विक गैस और तेल उत्पादकों पर महाद्वीप की निर्भरता को लेकर यूरोप में चिंताओं के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को कैसे तेज किया जाए विषय पर जलवायु वार्ताकारों के रूप में चर्चा के दौरान यह घोषणा की। मैक्रों ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा, 'फ्रांस की ईंधन स्वतंत्रता, देश में बिजली आपूर्ति की गारंटी और विशेष रूप से 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हम दशक में पहली बार अपने देश में पुनरू परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेंगे और अक्षय ऊर्जा का निर्माण जारी रखेंगे।' हालांकि उन्होंने योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। फ्रांस किसी भी अन्य देश की तुलना में परमाणु ऊर्जा पर अधिक निर्भर है।

नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना में मिली जनरल रैंक

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। भारत सरकार ने नेपाल के सेना प्रमुख को इंडियन आर्मी के ऑनरेरी जनरल की रैंक दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को नेपाली आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा को यह रैंक प्रदान की। प्रभु राम शर्मा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के आमंत्रण पर 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। बुधवार को उन्हें भारतीय सेना में जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। नेपाल सेना के प्रवक्ता की तरफ ने भारत की ओर से प्रभु राम शर्मा को दिए गए इस सम्मान के लिए प्रसन्नता जताई है। भारत दौरे पर प्रभु राम शर्मा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से मुलाकात करेंगे।

इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा को किया नाराज

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री इमरान खान ने टीएलपी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना इस फैसले से खुश नहीं है। डॉन की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। पाकिस्तान में तेजी से हो रहे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने टीएलपी मार्च करने वालों के खिलाफ बल प्रयोग को मंजूरी दी थी।

एक बार जब इस आदेश को जारी कर दिया गया, तो पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की ओर से इसका पालन किए जाने भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग के संभावित परिणामों की समीक्षा की की उम्मीद थी। हालांकि, उन्होंने भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग के संभावित परिणामों की समीक्षा की। उन्होंने इसका अनुमान लगाया कि मार्च करने वालों के खिलाफ बल लागू करने के लिए क्या करना होगा और कितने हताहत हो सकते हैं। यदि कानून लागू करने वाले अंतिम उपाय का उपयोग करते हैं और तितर–बितर होने से इनकार करने वालों पर गोलियां चलाते हैं। नेतृत्व ने इस गणना में हताहतों की संभावित प्रभावों और जनमत पर इसके प्रभाव का भी अध्यन किया। सूत्रों के अनुसार, सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के एकत्र होने पर टीएलपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बल प्रयोग के सभी पक्ष और विपक्ष प्रस्तुत किए।

इस बैठक की जानकारी रखने वाले लोगों ने डॉन को इस बात की पुष्टि की है कि सेना प्रमुख ने कहा था कि यदि निर्णय लेने वाले टीएलपी के खिलाफ बल प्रयोग के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार थे, तो सेना आदेश के अनुसार करेगी। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने 27 अक्टूबर को कैबिनेट को बताते हुए प्रधानमंत्री के हवाले से कहा था कि सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने और चुनौती देने की अनुमति नहीं देगी।

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का अपनी डपली, अपना राग

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर ट्रोइका प्लस बैठक बुलाई है जिसमें अमेरिका, चीन, रूस को बुलाया गया है। ये बैठक गुरुवार को होगी, जिसमें इन देशों के वरिष्ठ राजनयिक हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के ही मुद्दे पर बुधवार को दिल्ली में भी पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक चली। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। इसमें सात देश हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक के लिए चीन समेत पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन दोनों ने ही इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में जारी बैठक में ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, रूस, कजाखिस्तान, किर्गीस्तान के एनएसए शामिल हैं।